MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Issue Brief

# लोकतंत्र और यथास्थितिवाद के बीच थाईलैंड

ओमप्रकाश दास

सितम्बर 25, 2023

## Summary

मई 2023 में, थाईलैंड में एक सेना समर्थित चुनी हुई सरकार के पांच सालों के शासन के बाद एक महत्वपूर्ण आम चुनाव हुआ। नतीजों ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि राजनीतिक सुधार की वकालत करने वाली 'मूव फॉरवर्ड' पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, जबकि लंबे समय से एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी रही, 'फिउ थाई' पार्टी दूसरे स्थान पर रही। यह परिणाम सैन्य समर्थित प्रतिष्ठान के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था, जो थाई जनता के बीच परिवर्तन की तीव्र इच्छा का संकेत देता है। लेकिन नई सरकार एक बार फिर से सेना समर्थित राजनीतिक दलों के गठबंधन से ही बनी और सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी की भूमिका अप्रासंगिक बन गई। इसके पीछे संवैधानिक और सत्ता के तंत्र की भूमिका साफ दिखती है, जिसका बार-बार पुनर्गठन तो हुआ, इसके बावजूद, सेना और राजशाही जैसे वर्चस्वशाली प्रतिष्ठान अपने आप को लगातार निर्णायक स्थिति में बनाए हुए हैं।

## चुनाव, परिणाम और सरकार गठन का संघर्ष

मई 2023 में हुए आम चुनाव के क़रीब तीन महीनों के बाद, 22 अगस्त को 'फिउ थाई' पार्टी के श्रेथा थाविसिन को संसदीय मतदान में एक स्पष्ट जीत के बाद, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।[1] इस संसदीय मतदान में थाविसिन को दो-तिहाई  सदस्यों का समर्थन मिला और मई में हुए चुनाव के बाद कायम राजनीतिक गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई। इसी के साथ, थाईलैंड में एक नए गठबंधन की राजनीति का भी सूत्रपात हुआ। थाविसिन, पूर्व प्रधानमंत्रियों 'फिउ थाई' पार्टी के थाकसिन शिनावात्रा और यिंगलक शिनावात्रा के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं।[2]

मई 2023 के चुनाव के अंतिम परिणामों के बाद 'मूव फॉरवर्ड' पार्टी को 151 और 'फिउ थाई' पार्टी को 141 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं, तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया 'भूमजिथाई' पार्टी, जिसे 71 सीटें मिली तो 'यूनाईटेड थाई नेशन' को सिर्फ 36 सीटें मिली।[3] मई के चुनावों के पहले 'यूनाईटेड थाई नेशन' ही सत्ता में थी, जिसे सिर्फ 45 लाख वोट मिले, जबकि लोकप्रियता के घोड़े पर सवार 'मूव फॉरवर्ड' पार्टी को 1.44 करोड़ से ज्यादा और 'फिउ थाई' पार्टी को करीब 1.09 करोड़ वोट मिले।[4] 'यूनाईटेड थाई नेशन' पार्टी का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा कर रहे थे, जिन्होंने 2014 में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया था। प्रयुत चान-ओचा 2014 में थाईलैंड की सेना के कमांडर-इन-चीफ थे, जिसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने थे।[5]

दरअसल 500 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में से 400 सीटों पर आम चुनाव होते हैं, बाकी की 100 सीटें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर उन्हें आवंटित होती है।[6] चुनाव के दौरान पीटा लिमजारोएनराट की 'मूव फॉर्वर्ड पार्टी' के साथ आठ पार्टियों का गठबंधन

---

[1] **"Parliament Elects Srettha Prime Minister"**, *Bangkok Post*, 22 August 2023.

[2] Rebecca Ratcliffe, **"Srettha Thavisin: The Real Estate Tycoon Turned Thai Prime Minister"**, *The Guardian,* 23 August 2023.

[3] Nigel Walker, **"Thailand: 2023 General Election and Possible Outcomes"**, Research Briefing, UK Parliament, 20 June 2023.

[4] **"MFP Victory One for the History Books"**, *Bangkok Post*, 20 May 2023.

[5] **"Thailand Coup General Prayuth Chan-ocha named PM"**, *BBC News*, 21 August 2014.

[6] सितंबर 2021 से पहले, 350 सीटों पर ही सीधे आम चुनाव होते थे और 150 सीटों को पार्टी के मतों के आधार पर आवंटित किया जाता था। इस व्यवस्था को नेशनल असेंबली ने सितंबर 2021 में संशोधित कर दिया। जिसके बाद सीधे मतों द्वारा चुने

था, जिसमें 'फिउ थाई' पार्टी भी शामिल थी। यहाँ तक कि गठबंधन को प्रतिनिधि सभा में बहुमत से काफी ज्यादा 312 सीटें मिली थीं। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पीटा को प्रधानमंत्री बनने के लिए उच्च सदन यानी सीनेट का भी बहुमत हासिल करना था, जो संभव नहीं हो पाया। 250 सदस्यों वाली सीनेट में सिर्फ 13 सदस्यों ने पीटा के पक्ष में मतदान किया, जबकि 34 ने खिलाफ में मतदान किया, 159 सीनेट सदस्यों ने मतदान नहीं करने का विकल्प चुना तो बाकी के 43 सदस्य मतदान के लिए आए ही नहीं।[7] एक सदस्य ने मतदान के एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। "सीनेटरों की इतनी बड़ी संख्या में मतदान न करने के पीछे मतदान के दौरान गोपनियता के भंग होने और उससे जुड़ी हिंसा की आशंका भी एक कारण बताया गया। यहां तक कि सीनेट के अध्यक्ष ने सीनेट सदस्यों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस से अपील भी की थी।"[8]

बहरहाल, इस तरह पीटा को दोनों सदनों के संयुक्त बहुमत के आंकड़े 376 के मुकाबले सिर्फ 324 मत ही मिल पाए।[9] इसके बाद दूसरे दौर के मतदान के पहले ही उनकी सदस्यता और चुनावी नियमों को तोड़ने के आरोप लगे और इस तरह वह प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए। पीटा पर एक मीडिया कंपनी में शेयर रखने का आरोप था। उल्लेखनीय है कि संविधान के तहत सांसदों को मीडिया कंपनियों में हिस्सेदारी रखना ग़ैर-कानूनी है[10] लेकिन पीटा पर एक मीडिया कंपनी में शेयर रखने का आरोप है।

इस बार के चुनाव में 'मूव फॉरवर्ड' पार्टी का नेतृत्व युवा और लोकप्रिय नेता पिटा लिमजारोनार्त कर रहे थे, जिन्होंने वर्ष 2020 में ही पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की पृष्ठभूमि में 'फ्युचर फॉर्वर्ड' पार्टी है, जिसे 2020 में ही संवैधानिक कोर्ट ने भंग कर दिया था।[11] जबकि फिउ थाई का पार्टी का नेतृत्व पेतोंगतार्न शिनावात्रा कर रही थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं। वर्ष 2006 में सेना ने थाकसिन

---

जाने वाली सीटों की संख्या 400 और आवंटित किए जाने वाली सीटों की संख्या 100 ही रह गई। See Chalida Ekvitthayavechnukul, **"Thai Parliament Approves Election System Charter Change"**, *Associated Press*, 10 September 2021.

[7] Petra Alderman, **"Thailand's Tilt at Democracy"**, Australian Strategic Policy Institute, 18 July 2023.

[8] **"Senate Clarifies Absence of 33 Senators During Last Thursday's Prime Ministerial Vote"**, *National News Bureau of Thailand*, 18 July 2023.

[9] Koh Ewe, **"Thailand's Election Winner Fails First Parliament Vote to Become Prime Minister—What to Know and What Comes Next"**, *Time*, 13 July 2023.

[10] **"Charter Court Suspends Pita"**, *Bangkok Post*, 19 July 2023.

[11] **"About Us"**, Future Forward Party.

शिनावात्रा को सत्ता से बेदखल कर दिया था।[12] इसके पांच साल बाद वर्ष 2011 में, उनकी रिश्तेदार यिंगलक शिनावात्रा प्रधानमंत्री बनी थीं, लेकिन 2014 में सेना ने तख्तापलट कर उन्हें भी सत्ता से हटा दिया था।[13]

## चुनाव, नेशनल असेंबली, और सेना की छाया

'मूव फॉर्वर्ड पार्टी' ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में कई बड़े बदलावों को आगे बढ़ाने का दावा किया था जो 'राजशाही और सैन्य वर्चस्व की यथास्थिति' को चुनौती देते थे।[14] मसलन, पीटा ने उस क़ानून में सुधार की मांग की थी, जिसके तहत थाईलैंड के शाही परिवार को बदनाम करना एक संगीन अपराध है और इसके तहत 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सीनेट के सदस्यों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि यह राजशाही के लिए आलोचना के दरवाज़े खोलता है। दरअसल में, वर्ष 2017 में नए संविधान के लागू होने के बाद, राजा की संवैधानिक शक्तियों में वृद्धि की गई थी। राजशाही को मिले संरक्षण और शक्तियों में बेहद प्रमुख रहा, 'लेसे मैजेस्टे' कानून में हुआ बदलाव।[15] क़ानून में, ये संशोधन, राजशाही दंड संहिता की धारा 112 द्वारा संरक्षित है, जो कहती है कि "जो कोई भी राजा, रानी, उत्तराधिकारी या शासक को बदनाम करेगा, अपमान करेगा या धमकी देगा, उसे तीन से 15 साल की जेल होगी।"[16] तमाम बदलावों के अलावा 2017 का यह संविधान, राजशाही को पहले से ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है,[17] जिसमें राजा के पास किसी भी संवैधानिक संकट की स्थिति में खुद से कदम उठाने की शक्ति भी समाहित है। मई 2023 के चुनाव के बाद, संसद में सरकार गठन और प्रधानमंत्री चयन के गतिरोध की स्थिति में, प्रतिनिधि सभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 'फिउ थाई' ने 'मूव फॉरवर्ड पार्टी' के साथ गठबंधन तोड़, दूसरे दलों का समर्थन हासिल किया। इसी के

[12] Wassana Nanuam, **"2006 Coup a Success, Claims Mastermind Sonthi"**, *Bangkok Post*, 19 September 2021.

[13] **"Thailand Military Seizes Power in Coup"**, *BBC News*, 22 May 2014.

[14] Sreeparna Banerjee, **"Thailand Votes towards a Transformative Agenda"**, Observer Research Foundation, 16 May 2023.

[15] Sebastian Strangio, **"Thai Opposition Coalition Unveils 23-Point Policy Platform"**, *The Diplomat*, 23 May 2023.

16 Jeffrey Hays, **"Thailand's Lese Majeste Laws"**, *Facts and Details*.

[17] **"Draft Constitution of the Kingdom of Thailand 2016 Unofficial English Translation"**, United Nations Thailand, Office of the United Nations Resident Coordinator, Thailand, 1 July 2016.

बाद, इस तरह श्रेथा थाविसिन के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। 'फिउ थाई' पार्टी ने यह साफ कर दिया कि दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के लिए यह ज़रूरी था कि 'मूव फॉरवर्ड' को गठबंधन से बाहर रखा जाए। अब नए गठबंधन में 11 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें दो वह पार्टियां भी शामिल हैं, जो सेना की समर्थक मानी जाती हैं।[18] इनमें से एक पार्टी है 'पलांग प्रचारत पार्टी' (पीपीपी), जिसके पास 40 सीटें हैं और दूसरी है पूर्व प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा के नेतृत्व वाली पार्टी 'यूनाइटेड थाई नेशन पार्टी' (यूटीएन), जिसे सिर्फ 36 सीटें मिली हैं। सेना समर्थक पीपीपी को एक सिविल-सैन्य राजनीतिक पार्टी माना जाता है, जिसका गठन 2018 में उन लोगों ने किया था, जो 2014 के तख्तापलट के बाद सैन्य सरकार में शामिल थे।[19]

इस दौरान जिस एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था सरकार के गठन के गतिरोध के बीच, थाकसिन शिनवात्रा का निर्वासन से वापस थाईलैंड लौटना। थाकसिन की स्वदेश वापसी के तुरंत बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन पर पहले से ही कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप थे।[20] बहरहाल, थाकसिन ही वह राजनेता थे जिनके राजनीतिक दल और उनसे जुड़े अन्य राजनीतिक दलों ने 2001 से 2019 के बीच लगातार चुनावों में जीत दर्ज की।[21] इसी के बाद, परंपरागत राजशाही और सैन्य वर्चस्व के लिए थाकसिन-गठबंधन वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर रखना एक चुनौती बन गई। इसी बीच 2006 और 2014 के तख्तापलट के बाद, थाईलैंड में सैन्य और राजशाही का गठजोड़, अलोकतांत्रिक राजनीति के प्रतीक की तरह स्थापित होता दिखा, विशेषकर युवाओं के सामने। ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि 15 साल के निर्वासन के बाद, थाकसिन उसी दिन देश लौटे, जिस दिन नेशनल असेंबली ने श्रेथा को प्रधानमंत्री चुना। अगस्त 2023 के अंत तक थाकसिन की सज़ा घटाकर एक साल कर दी गई ।[22] यह क्षमादान इस बात को समझने के लिए पर्याप्त संकेत देते हैं कि 'मूव फॉर्वर्ड' पार्टी को छोड़, नए गठबंधन के लिए 'फीयू थाई' ने वर्चस्वशाली प्रतिष्ठान के साथ तालमेल बनाया है।

---

[18] Francesca Regalado, **"Thailand's Pheu Thai Coalition Adds Largest Pro-military Party"**, *Nikkei Asia*, 21 August 2023.

[19] Ibid.

[20] **"Ex-PM Thaksin Sentenced to 8 years' Jail on Return to Thailand from Exile"**, *Channel News Asia*, 22 August 2023.

[21] Tan Tam Mei, **"In Thailand, Shinawatra Legacy Endures in Family-linked Party as Election Looms"**, *The Straits Times*, 5 March 2023.

[22] Rebecca Ratcliffe, **"Thai King Reduces ex-PM Thaksin Shinawatra's Prison Sentence to One Year"**, *The Guardian*, 1 September 2023.

## लोकतंत्र का आगमन और विरोधाभास का इतिहास

थाईलैंड में मौजूदा चक्री वंश की राजशाही वैसे तो वर्ष 1782 से शुरू होती है,[23] जिसे 20वीं सदी में वहाँ के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के रूप में एक चुनौती का सामना करना पड़ा। वर्ष 1932 में इस देश ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, पूर्ण राजशाही को समाप्त किया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। तब से लेकर आज तक इस देश में तख्तापलट की 19 कोशिशें हो चुकी हैं,[24] जिनमें से 13 को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है।[25] पहला तख्तापलट तो संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के एक साल के बाद ही हो गया था। वर्ष 1933 में 'बोवोराडेट विद्रोह'[26] हुआ और सत्तारूढ़ 'पीपुल्स पार्टी' को एक सैन्य-नौकरशाह गठबंधन ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तख्तापलट का उद्देश्य पूर्ण राजशाही को बहाल करना था। एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1948 से लेकर 1991 तक ज्यादातर प्रधानमंत्री सेना के जनरल / शीर्ष अधिकारी ही हुए हैं। सत्तारूढ़ सैन्य शासकों ने अक्सर संविधान को निरस्त किया है, यहां तक कि 2017 में एक नया संविधान ही लागू कर दिया। इस तरह से थाईलैंड में अब तक कुल 20 अलग-अलग चार्टर और संविधान अस्तित्व में आए हैं।[27] मौजूदा वक्त में ,थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें राजा देश का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।[28] हालांकि 2017 के नए संविधान के बाद से सेना ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपनी एक अप्रत्यक्ष पहचान बनाई है।[29]इतिहास बताता है कि पिछले 90 सालों में राजशाही समय-समय पर, अपने नैतिक अधिकार का उपयोग राजनीतिक संकटों को हल करने और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए करती रही है। संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री के पास सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा, राजशाही और सेना हमेशा ही एक संतुलन में काम करते रहे हैं।[30] राजनीतिक

---

[23] Anthony Reid, *A History of Southeast Asia: Critical Crossroads*, John Wiley & Sons, 2015, p. 215.

[24] Nicholas Farrelly, **"Thailand's Elite Coup Culture"**, Australian Institute of International Affairs, 28 March 2014.

[25] Sreeparna Banerjee, **"Thailand's Persisting Prime Ministerial Dilemma"**, Observer Research Foundation, 16 August 2023.

[26] Thanavi Chotpradit , **"Countering Royalism with Constitutionalism"**, *South East Asia Research*, Vol. 26, No. 3, 18 October 2018, pp.–255-235.

[27] **"With 20 Constitutions, Thailand Joins a Select League"**, *The Nation*, 10 June 2017.

[28] **"Thailand in Brief"**, Royal Thai Embassy, Washington D.C.

[29] **"Thailand Country Report 2022,"** BTI Transformation Index.

[30] **"Thailand in Brief"**, Royal Thai Embassy, Washington D.C.

उथल-पुथल के बावजूद, थाईलैंड ने लगातार जवाबदेही, पारदर्शिता, सुशासन, मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है जिसका एक उदाहरण ,बहुदलीय लोकतंत्र भी है।[31] लेकिन करीब 9 दशक पहले 1932 में हुई लोकतांत्रिक क्रांति की अपनी एक विशेष पृष्ठभूमि है जिसमें तत्कालीन आर्थिक मंदी ('ग्रेट डिप्रेशन'), सामाजिक बदलाव की आकांक्षाएं, आम लोगों का कुलीन वर्गों से भारी मोहभंग आदि कुछ बड़े कारक थे। जिसका परिणाम, राजशाही की पूर्ण पकड़ के ढीले होने और संवैधानिक राजशाही की स्थापना के रूप में देखने को मिलता है। थाईलैंड में 'पीपल्स पार्टी' के नेतृत्व में लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत 24 जून 1932 को हुई। जून 1932 में लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद, लोकतांत्रिक शक्तियों ने सत्ता संभाली और प्रधानमंत्री की नियुक्ति को सुनिश्चित किया। जिसके बाद ही एक नया संविधान भी अस्तित्व में आया, लेकिन चुनावों के पहले ही अक्टूबर, 1933 में प्रिंस बोवोराडेट ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और देश में सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। लेकिन, तब से लेकर आज तक, देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत स्थिर न रह सकीं। हालांकि 1990 के दशक में राजनीतिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति ने जनता और वंचितों के बीच तेजी से सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरूकता को पैदा तो किया लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक-सैन्य-राजशाही के ढांचे में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो पाया। लेकिन वर्चस्वशाली शक्तियों ने नए संविधान को वर्ष 2017 में पूरी तरह लागू ज़रूर कर दिया, जिसने अर्ध-प्रभु-सत्तावादी शासन तंत्र को स्थाई बना दिया।

## राजशाही और सेना के संबंध और लोकतंत्र की आवाज़

वर्ष 1949 के बाद से ही, देश में छुटपुट लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन 1973 में लोकतंत्र समर्थक छात्रों पर सैन्य सरकार की दमनात्मक कार्रवाई में में 77 लोग मारे गए। जिसके बाद, राजा के दखल के बाद सैन्य सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तब एक बार फिर से लगा कि लोकतांत्रिक शासन का दौर अपनी जगह बना रहा है। लेकिन, 1976 में एक बार फिर से सैन्य तख्तापलट हुआ। वर्ष1992 में विरोध प्रदर्शनों पर हुई दमनात्मक कार्यवाही में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। 2001 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बल पर थाकसिन शिनावात्रा प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन, साल 2006 आते-आते सेना ने, थाकसिन को सत्ता से

[31] Ibid.

बेदखल कर दिया, फिर भी 2007 के चुनाव में थाकसिन की गठबंधन पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद 2008 से लेकर अगले कुछ सालों तक कभी थाकसिन के विरोधी 'येलो शर्ट्स' समूह ने, तो कभी समर्थक 'रेड शर्ट्स' धड़े ने, राजधानी बैंकॉक में विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्ज़े के कई अभियानों का नेतृत्व किया। साल 2010 में इन प्रदर्शनों के दौरान 90 लोगों की मौत हुई। 2011 के आम चुनाव में एक बार फिर से थाकसिन की सहयोगी पार्टी 'फिउ थाई' ने भारी बहुमत से चुनाव जीता, लेकिन इसके बाद भी थाकसिन विरोधी अभियानों का दौर थमा नहीं। अस्थिरता के इस माहौल के बीच, वर्ष 2014 में तत्कालीन सेना प्रमुख प्रयुत चान-ओचा ने सैन्य तख्तापलट किया और खुद ही देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। 2017 में, सेना ने एक नया संविधान पेश किया, जिसने सेना को 250 सदस्यीय सीनेट नियुक्त करने की शक्ति दी। इसके बाद, वर्ष 2019 में संसदीय चुनाव हुए, जिसे सैन्य शासन से निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की एक कवायद के रूप में देखा गया। इस चुनाव में प्रयुत की नई सेना समर्थक पार्टी को विजेता घोषित किया गया था। लेकिन विपक्षी दलों की शिकायत रही कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई थी। तब से लेकर मई 2023 के चुनाव तक प्रयुत सत्ता पर काबिज रहे।

इतिहास इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि थाई सेना और राजशाही का एक लंबा और आपस में जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। सच यह है कि सेना ने राजशाही की शक्ति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और राजशाही ने सैन्य शासन का समर्थन करने के लिए अपने प्रभाव का समय-समय पर उपयोग किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि थाईलैंड में एक ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें सेना और राजशाही अपनी शक्ति और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं।[32] सेना खुद को राजशाही और देश की स्थिरता का संरक्षक मानती है तथा इन हितों की रक्षा के लिए अक्सर राजनीति में हस्तक्षेप करती है। इस तरह तख्तापलट, लोकतंत्र का निलंबन और सैन्य प्रभाव को बनाए रखने वाले संवैधानिक परिवर्तनों का दौर भी लगातार चलता रहा है।[33] इन हस्तक्षेपों के साथ नागरिक स्वतंत्रता और मीडिया नियंत्रण पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। राजशाही ने सेना के तख्ता पलट को वैधता भी देती रही है, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जब राजशाही ने लोकप्रिय आंदोलनों के सामने सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। उदाहरण के

[32] Indrė Balčaitė and Christian Gilberti, **"Recurring Coups in Myanmar and Thailand: Military as Monarchy and the Military-monarchy Nexus"**, *LSE Southeast Asia Blog*, 9 February 2021.

[33] Pavin Chachavalpongpun, **"Why Thailand's New Military-Monarchy Alliance is a Bad Sign for Democracy"**, *The Diplomat,* 25 June 2019.

लिए, 1973 में, राजा भूमिबोल अदुल्यादेज ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ छात्रों के विरोध को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप किया।[34] उन्होंने सैन्य नेताओं से भी बात की और उन्हें पद छोड़ने के लिए मनाया। इससे थाईलैंड में लोकतंत्र की बहाली हुई। फिर वर्ष 1981 में, राजा भूमिबोल ने एक सैन्य तख्तापलट का समर्थन करने से इनकार कर दिया।[35] लेकिन पिछले लगभग 90 वर्षों के इतिहास में इन घटनाओं को अपवाद के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास का ज्यादातर हिस्सा ऐसा रहा है जहां थाई राजशाही लोकतंत्र की तुलना में सेना के अधिक समर्थक रहे हैं।[36] सेना और राजशाही के संबंधों का एक उदाहरण,वर्ष 2006 के तख्तापलट की घटना में देखा जा सकता है। उस वक्त सेना-राजशाही वर्चस्व और राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देने के कारण लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। वहीं, वर्ष 2014 के तख्तापलट के बाद फिर लोकतांत्रिक सरकार को हटाया गया, जिसका उद्देश्य था, 2016 में राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के निधन के बाद, शाही उत्तराधिकार की तैयारी में राजशाही की रक्षा करना और उसे मजबूत करना। इसका करना यह था कि राजा भूमिबोल के उत्तराधिकारी राजा वजिरालोंगकोर्न की जनता में छवि और क्षमता पर कई सवालिया निशान थे।[37] यही वह समय था जब सेना ने हालात को भांपते हुए वर्ष 2017 में, संविधान में संशोधन किया और राजा की भूमिका को सीमित करते हुए सेना के अप्रत्यक्ष वर्चस्व को मज़बूत किया। इसका एक उदाहरण 2023 के लोकतांत्रिक चुनाव और फिर प्रधानमंत्री के चयन में ग़ैर-लोकतांत्रिक शक्तियों की निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। थाईलैंड के समाज का एक वर्ग, विशेष रूप से युवा थाई लोग, राजशाही की भूमिका, उसके विशेषाधिकारों और शक्तियों पर सवाल उठाते रहे हैं। वर्ष 2020 में एक व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें अधिकांश प्रदर्शनकारी छात्र और युवा औसतन 20 वर्ष आयु वर्ग के थे। उन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी राजशाही व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राजा की संपत्ति और क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो (थाईलैंड में सम्राट की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए अर्ध-सरकारी संस्थान) को अलग करना, राष्ट्रीय बजट में महल के हिस्से में कटौती, राजा पर अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने पर

[34] **"Thai Students Overthrow Military Thanom Regime, 1973"**, Global Nonviolent Action Database, 14 September 2023.

[35] Larry A. Niksch, **"Thailand in 1981: The Prem Government Feels the Heat"**, *Asian Survey*, Vol. 22, No. 2, 1982, pp. 191–199.

[36] Joshua Kurlantzick, **"Thailand Protests Increasingly Challenge the Monarchy"**, Council on Foreign Relations, 18 August 2020.

[37] Pavin Chachavalpongpun, **"Why Thailand's New Military-Monarchy Alliance is a Bad Sign for Democracy"**, no. 33.

प्रतिबंध और भविष्य में तख्तापलट का समर्थन करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय। नवंबर 2020 में हुए इन लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के दौरान संविधान संशोधन पर ज़ोर दिया गया और दस-सूत्रीय मांगे रखी गयी जिसमें मुख्य रूप से संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा की भूमिका में बदलाव की मांग थी, ताकि वह जनता के प्रति और जिम्मेदार बन सके। एक मांग यह भी थी कि सेना और राजदरबार के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाहर कोई सांठ-गांठ न हो।[38]

## संविधान और लोकतंत्र

नेशनल काउंसिल फॉर पीस एंड ऑर्डर (एनसीपीओ) ने मार्च 2016 में नए संविधान का एक मसौदा जनता के सामने रखा, जिस पर अगस्त 2016 को जनमत संग्रह हुआ। लेकिन इस जनमत संग्रह से पहले, थाईलैंड की सेना ने जनमत संग्रह के बारे में कोई भी प्रचार करने एवं चर्चा करने पर रोक लगा दी। यहां तक कि 'जनमत संग्रह अधिनियम' (अनुच्छेद 61)[39] के तहत कई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल 'जनमत संग्रह अधिनियम' किसी भी मीडिया को 'झूठी सूचना' फैलाने से रोकता है जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है।[40] दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ यह अधिनियम 10 साल तक की जेल और 200,000 बाट (थाईलैंड की मुद्रा) तक के जुर्माने का प्रावधान करता था।[41] जनमत संग्रह की इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ और कई देशों के राजदूतों ने सख्ती पर चिंता व्यक्त की थी।[42] इस जनमत संग्रह में थाईलैंड के 59.4 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया,[43] उसमें से नए संविधान के पक्ष में केवल 61.3 प्रतिशत थाई मतदाताओं ने मत दिया।[44]

---

[38] राहुल मिश्र, **"थाईलैंड में बढ़ती जा रही है लोकतंत्र की मांग"**, DW, 13 November 2020.

[39] Duncan Mccargo, Saowanee T. Alexander and Petra Desatova, **"Thailand's 2016 Constitutional Referendum"**, *Contemporary Southeast Asia,* Vol. 39, No. 1, ISEAS - Yusof Ishak Institute, April 2017, pp. 65–95.

[40] Ibid.

[41] Nirmal Ghosh, **"Thai Military's Grand Design in Politics"**, *Straits Times*, 5 April 2016.

[42] Adam Ramsey, **"Thailand Constitutional Referendum: All Your Questions Answered"**, *The Guardian,* 3 August 2016.

[43] Duncan Mccargo, Saowanee T. Alexander and Petra Desatova, **"Thailand's 2016 Constitutional Referendum"**, no. 39.

[44] Ibid.

थाईलैंड के संविधान (2017) की धारा 111 (भाग 3) यह बताती है कि 250 सदस्यों वाली सीनेट में सदस्यों का 'चुनाव' नहीं 'चयन' होगा।[45] 2017 के संविधान का यह प्रावधान, प्रतिनिधि सभा पर भी अपना असर डालता है और प्रधानमंत्री के चयन में भी इसकी भूमिका होती है। वहीं, सीनेट के मौजूदा सदस्यों की पृष्ठभूमि चर्चा का विषय रही है। सीनेट के 250 सदस्यों में से कम से कम 160 या क़रीब दो-तिहाई सदस्य सैन्य या पुलिस की पृष्ठभूमि वाले या शासन-सत्ता के करीबी हैं।[46] मूव फॉर्वर्ड' पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पीटा लिमजारोएनराट के संदर्भ में सीनेट की इस निर्णायक शक्ति को दुनिया देख चुकी है।[47] 'नया' संविधान (धारा 156) इस बात का भी उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव में नेशनल असेंबली का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है।[48] साथ ही, संवैधानिक प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करते है कि प्रधानमंत्री का चयन तब तक नहीं हो सकता, जब तक 500 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली के साथ साथ उच्च सदन यानी सीनेट में भी बहुमत न मिल जाए। जिसका कुल आंकड़ा 376 तक पहुंचता है।[49]

इन नए प्रावधानों के अनुसार "सेना की समिति (एनसीपीओ) कुल 194 लोगों को सीधे-सीधे चुनेगी। इसके अलावा 6 अन्य लोग जिसमें सुप्रीम कमांडर-इन-चीफ, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख, रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव भी होंगे, खुद-ब-खुद ही सीनेट के सदस्य बन जाएंगे, यानी जो भी इन पदों पर बैठा हो, वो सीनेट का सदस्य होगा। इसके अलावा सीनेट के शेष सदस्यों का चुनाव, सीनेट और राजा खुद या सैन्य शासक करते हैं।[50] बाकी बचे 50 सीनेटरों में से 10 पेशेवर और 40 सदस्य अलग-अलग सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें नौकरशाह, शिक्षक, न्यायाधीश, किसान और निजी कंपनियों के लोग शामिल हो सकते हैं।[51] इस प्रक्रिया के तहत ही वर्ष 2017 में सीनेट सदस्यों का 'चयन' हुआ था। जिसमें इन 50 सदस्यों के 'चयन' प्रक्रिया में 2,746 उम्मेदवार थे जिनमें से अधिकांश नामों को हटाने

[45] निर्वाचित का अर्थ है किसी कार्यकारी, विधायी या न्यायिक कार्यालय को भरने के लिए सामान्य या विशेष चुनाव में वोट द्वारा चुना गया कोई भी व्यक्ति। नियुक्त का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी वैकल्पिक कार्यालय या अंतरिम कार्यालय पद को भरने के लिए )आमतौर पर बोर्ड या परिषद द्वारा( नियुक्त किया जाता है।

[46] **"Senators Seen as PM Puppets"**, *Bangkok Post*, 15 May 2019.

[47] **"Constitution of the Kingdom of Thailand"**, 2017.

[48] **"Section 156, Thailand's Constitution of 2017"**, Constitute Project, 29 January 2019.

[49] Helen Regan and Kocha Olarn, **"Critical Moment for Thai Democracy as Parliament Fails to Elect New Prime Minister"**, *CNN*, 13 July 2023.

[50] **"Section 269, Thailand's Constitution of 2017"**, Constitute Project, 29 January 2019.

[51] Ibid.

के बाद,शीर्ष 200 उम्मीदवारों की एक सूची बनी, जिनकी पृष्ठभूमि की जांच चुनाव आयोग ने की। इसके बाद एनसीपीओ ने 50 को सीनेटर को सीधे चुना।[52] वर्ष 2020 तक की जानकारी बताती है कि 250 सीनेटरों में से 104 पुलिस या सैन्य अधिकारी हैं।[53]

## लोकतांत्रिक अस्थिरता,वर्चस्वशाली शक्तियां और भविष्य

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के बल पर ही आगे बढ़ती और फलती-फूलती है, आम मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी उसका एक अहम हिस्सा है। लेकिन थाईलैंड में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति, यह स्पष्ट करती है कि कैसे शासन में भागीदारी करने वाली संवैधानिक संस्थाओं के बल पर जनादेश को एक हद तक सीमित किया जा सकता है। पूर्ण राजशाही की समाप्ति के बाद से निर्वाचित सरकारों को उलटने-पलटने का जो दौर 1932 के बाद से शुरू हुआ, आज वह एक नया स्वरूप ले चुका है। राजशाही और सेना की वर्चस्वशाली शक्तियों को अब सीधे-सीधे सरकारों को गिराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यह काम संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही अंजाम दिया जा सकता है। थाईलैंड इस बात की बानगी पेश करता है कि कैसे लोकतंत्र की आकांक्षा, राजशाही की सत्ता पर पकड़ बनाते हुए संतुलन साधने की कोशिशें और देश की आंतरिक राजनीति में सेना की लगातार निर्णायक उपस्थिति, सतत संघर्ष और अस्थिरता का कारण बना हुआ है। इतिहास इस ओर भी इशारा करता है कि कैसे थाईलैंड ने नौ दशक पहले लोकतंत्र की तरफ कदम तो बढ़ाए, लेकिन वह अब तक देश के मूलभूत ढांचे में अपनी स्थाई स्थिति को कायम नहीं कर पाया है। ताज़ा लोकतांत्रिक चुनाव, जनादेश का इशारा और अंत में सरकार का गठन अपने आप में विरोधाभास को समेटे है, जो मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार के स्वरूप और दिशा पर संदेह पैदा करता है। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा, अभी भी अपनी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है।

---

[52] Dave Kendall, **"Explainer: The Appointed Senate"**, *Bangkok Post*, 4 January 2023.

[53] **"Gen Prayut's Brother Appointed to Military-dominated Tourism Committee"**, *Prachatai English,* 17 April 2020.

## About the Author

**Mr. Om Prakash Das** is Research Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

**Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses** is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

*Disclaimer:* Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2023

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses